



**कार्यालय—प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।**

**E-Mail ID: nodalofficerddn@gmail.com, Phone/Fax: 0135 2767611
पत्रांक— २५८। / १२-१ :देहरादून:दिनांक: १९ अप्रैल, 2025**



नेशनल कॉर्पोरेशन

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
वन एवं पर्यावरण,
उत्तराखण्ड शासन।

वन अनुभाग—०३

**विषयः—जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र डीडीहाट में बुंगाछीना धौनखोल रसैपाटा मोटर मार्ग हेतु ०.८१ है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।
(ऑनलाइन प्रस्ताव संख्या—FP/UK/ROAD/42150/2020)**

संदर्भः—वन एवं पर्यावरण अनुभाग—०३, उत्तराखण्ड शासन की पत्र संख्या 859/X-3-20/1(95)/2020 दिनांक 07.08.2020.

महोदय,

उत्तराखण्ड शासन के उपर्युक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का संज्ञान लेने का कष्ट करें, जिससे उत्तराखण्ड शासन द्वारा विषयांकित प्रकरण में कतिपय शर्तों के तहत सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है। सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों की अनुपालन आख्या प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़ की पत्र संख्या—५५६२/१२-१ दिनांक 17.03.2025 (प्रति संलग्न) के द्वारा इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गई है जो कि निम्नानुसार संलग्न कर प्रेषित की जा रही है:-

क्र० सं०	अधिरोपित शर्त	सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या
1.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल के आस-पास रिक्त पड़े स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों पर समाहित करने हेतु यथा संशोधित) जमा की जाएगी।	प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़ द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्तावक विभाग द्वारा आस-पास रिक्त पड़े स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख रखाव हेतु आवश्यक धनराशि रु० 1,33,100.00 मात्र जमा करा दी गई है। (संलग्नक-१)
2.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन सिविल 202/1995 के अंतर्गत आर्ड० १०सं०—५६६ एवं भारत सरकार पत्र संख्या—५-३/२००७—एफ०सी० दिनांक 05.02.2009 के तहत दिए गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन०पी०वी०) की निर्धारित राशि जमा की जाएगी।	प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़ द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन सिविल 202/1995 के अंतर्गत आर्ड०१०सं०—५६६ एवं भारत सरकार पत्र संख्या—५-३/२००७—एफ०सी० दिनांक 05.02.2009 के तहत दिए गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन०पी०वी०) की निर्धारित राशि रु० 5,32,170.00 मात्र जमा करा दी गयी है। (संलग्नक १ के अनुसार)
3.	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन०पी०वी० की दर में बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जाएगी।	प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त मान्य है। (संलग्नक-२)
4.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार पत्र संख्या—५-३/२००७—एफ०सी०, दिनांक 05.02.2009 के तहत दिए गये आदेशों के अनुसार एन०पी०वी० तथा दूसरी अलग निधियों प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के लेखा संख्या—एस०वी०—२५२२९ कार्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपकर्म), ब्लॉक-११ भूतल सी०जी०आ० कॉम्प्लेक्स फेज-०१ लोधी रोड नई दिल्ली— ११०००३ में जमा कराने के उपरान्त ही पावती की छायाप्रति जमा की गई। धनराशि का बैंक ड्राफ्ट/चैक की छायाप्रति सहित प्रस्ताव के सन्दर्भ में अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गई धनराशि का मदवार विवरण अर्थात् एन०पी०वी०, क्षतिपूरक वृक्षारोपण प्रस्तावित स्थल के आस-पास वृक्षारोपण तथा अन्य देय धनराशियों का विवरण दिया गया हो) उपलब्ध कराए जाने के पश्चात ही निर्गत स्वीकृति मान्य होगी।	प्रस्तावक विभाग द्वारा एन०पी०वी० तथा प्रस्तावित स्थल के आस-पास वृक्षारोपण हेतु जमा की गई धनराशि की पावती की छायाप्रति व ड्राफ्ट की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित है। (संलग्नक १ के अनुसार)

5.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित निर्माण कार्य के लिए जनपद कार्यबल की संस्तुतियों एवं भू-वैज्ञानिक के सुझावों का कड़ाई से अनुपालन किया जाएगा।	प्रस्तावक विभाग द्वारा भू-वैज्ञानिक की शर्त मान्य होने का प्रमाण पत्र संलग्न कर प्रेषित है। (संलग्नक-3)
6.	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा वन अधिकार अधिनियम 2006 के अंतर्गत आवश्यक अभिलेखों/प्रमाण पत्रों को उपलब्ध कराया जाना होगा।	प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रपत्र संलग्न कर प्रेषित है। (संलग्नक-4)
7.	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा प्रस्ताव में निहित किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन नहीं होने अथवा असंतोषजनक अनुपालन होने की स्थिति में राज्य सरकार, पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।	प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त मान्य है।
8.	उपरोक्त शर्तों के अनुपालन पश्चात प्रकरण में विधिवत स्वीकृति निर्गत की जाएगी।	प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त मान्य है।

अतः सूचना संलग्न कर इस आशय से प्रेषित कि जा रही है कि प्रश्नगत प्रकरण में प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़ द्वारा प्रेषित सूचना के क्रम में प्रकरण पर वन (संरक्षण एवं संर्वधन) अधिनियम, 2023 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति हेतु भारत सरकार को अग्रसारित करना चाहें।

संलग्न—उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(आर०के० मिश्र)

प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या : २५८१ / 12-1 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड अल्मोड़ा।
- प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।
- अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, पिथौरागढ़।

(आर०के० मिश्र)

प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

संलग्नक - 1

DPY



UNION BANK OF INDIA
ANDHRA
PITORAGARH

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 04-07-2023

Agency Name.	PUBLIC WORK DEPARTMENT
Application No.	6142150020
MoEF/SG File No.	1(95)/2020
Location.	UTTARANCHAL
Address.	PD PWD PITHORAGARH GHANTAKARAN DISTT PITHORAGARH 262501 Pithoragarh
Amount(in Rs)	665270/-

Amount in Words : Six Lakh Sixty-Five Thousand Two Hundred and Seventy Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	150896142150020 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre, 21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

Note: After making the required payment through challa even after 7 working days, then kindly mail a copy of your Challan to Email: fcsblr@unionbankofindia.bank , epurse@unionbankofindia.bank , ubin0903710@unionbankofindia.bank

① Cheque No 956828 dt 13/3/2023 ₹ 665270.00

② Cheque No 956898 dt 26/6/23 ₹ 539170.00

665270.00
अधिकारी अधिकारी
मान्य सुपरिवर्तन
पिठोरागढ़

5. Date of start
6. Date of completion

20/03/2023

20/03/2023

20/03/2023

20/03/2023

20/03/2023

प्रारूप-51

परियोजना का नाम:- माननीय मुख्य मंत्री घोषणा के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र डीडीएट में बुंगाईना धौनखोला रसैफाटा मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।

एनोपी०वी० की बढ़ी दरों के अनुसार अतिरिक्त धनराशि जमा कराये जाने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि यदि भविष्य में मा० उच्चतम न्यायालय/भारत सरकार द्वारा एनोपी०वी० की वर्तमान दरों में कोई बढ़ोतरी की जाती है तो एनोपी०वी० की बढ़ी हुई धनराशि का भुगतान वन विभाग को यथासमय कर दिया जायेगा।

सहायता आवधन
प्रान्तीय सचिव सोनिलेखन
पिथौरागढ़

प्रान्तीय खण्ड लो०निर्दिश
पिथौरागढ़

परियोजना का नाम:-

माननीय मुख्य मंत्री घोषणा के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र डीडीहाट में बुँगाछीना धौनखोला रसैपाटा मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।

भू-वैज्ञानिक की संस्कृतियों/सुझावों का अनुपालन किये जाने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि विषयगत परियोजना के निर्माण हेतु भू-वैज्ञानिक द्वारा दिये गये सुझावों/संस्कृतियों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

अधिकारी/भूपत्र
प्रान्तीय खण्ड/लोकनिर्माण
(प्रयोक्ता/प्रयोक्ता)

प्रारूप-30.3

परियोजना विवरण :- माननीय मुख्य मंत्री घोषणा संख्या 37/2015 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र डीडीहाट मे बुंगाछीना धौनखोला से रसैपाटा मोटर मार्ग का का नव निर्माण कार्य।

कार्यालय जिलाधिकारी, पिथौरागढ़

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रभाण-पत्र

जिला स्तरीय समिति, पिथौरागढ़

जिला पिथौरागढ़ परिक्षेत्र के अन्तर्गत माननीय मुख्य मंत्री घोषणा संख्या 37/2015 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र डीडीहाट मे बुंगाछीना धौनखोला से रसैपाटा मोटर मार्ग का का नव निर्माण कार्य (शून्य हो आरक्षित वन भूमि, 0.810 हे0 सिविल एवं सोयम वन भूमि 0.00 हे0 वन पंचायत भूमि, अर्थात कुल 0.810 हे0 वन भूमि) का प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग पिथौरागढ़ प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील कनालीछीना) की दिनांक 31.08.2018 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत जिला स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री सी० रविशंकर जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष जिला स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपरिथित निम्नानुसार है।

1- श्री सी० रविशंकर जिलाधिकारी पिथौरागढ़ अध्यक्ष

2- श्री ~~पुरुषोदाम~~ प्रभागीय वनाधिकारी पिथौरागढ़ सदस्य

3- श्रीमति मंजूला देवी पत्नी श्री महेन्द्र सिंह ग्राम सिर्दार्ग धारचूला जिला पंचायत सदस्य

4- श्री कमलेश आर्या पुत्र श्री प्रेम राम ग्राम जैती विकास खण्ड मुनरस्यारी जिला पंचायत सदस्य

5- श्री अमर वहादुर चन्द्र पुत्र श्री लक्ष्मी चन्द्र ग्राम दुर्तीबगड जौलजीबी विकास खण्ड धारचूला जिला पंचायत सदस्य

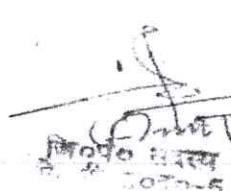
6- श्री ~~द्वारा~~ जिला समाज कल्याण अधिकारी पिथौरागढ़ सदस्य/सचिव

जिला सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में रवागत करते हुए जिलाधिकारी की अनुमति बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि माननीय मुख्य मंत्री घोषणा संख्या 37/2015 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र डीडीहाट मे बुंगाछीना धौनखोला से रसैपाटा मोटर मार्ग का का नव निर्माण कार्य परियोजना हेतु 0.810 हे0 वन भूमि प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग पिथौरागढ़ प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लियत नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में जिला स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से जिला पिथौरागढ़ परिक्षेत्र के अन्तर्गत माननीय मुख्य मंत्री घोषणा संख्या 37/2015 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र डीडीहाट मे बुंगाछीना धौनखोला से रसैपाटा मोटर मार्ग का का नव निर्माण कार्य परियोजना के निर्माण हेतु 0.810 हे0 वन भूमि प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग पिथौरागढ़ प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

अतः प्रकरण में जिला स्तरीय वनाधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।



मुख्यमंत्री

मिशन भवन
प्रिंसिपल



(वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत समस्त वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्रों पर सूचना/अभिलेख संलग्न किये जाने हैं।)

FORM-1

(for linear projects)

Government of Uttarakhand

Office of the District Collector Pithoragarh

No--- 36

Dated-- 31/8/13

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **0.810** hectares of forest land proposed to be diverted in favour of **Public Work Department** for in Pithoragarh district falls within jurisdiction of Batula(Musgal, Dhaunkhola) village(s) in Kanalichina (Pithoragarh) tehsils.

It is further certified that:

- (a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **0.810** hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure ...to ...annexure....
- (b) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it;
- (c) the proposal does not involve recognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Eucl: As above.

Signature

(Full name and official seal of the District Collector)

**OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER
DISTRICT PITHORAGARH (U.K.)**

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of Pithoragarh district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mr/Mrs/Miss. ~~G.Ravi Sanjay~~ S deputy commissioner, ~~Pithoragarh~~ dated ~~3.1.8.08~~ at time~~4:00~~ at ..P.M., in which application claiming rights in area measuring 0.810 hect for the construction of Bungachina-Raseapata to Batula (Musgal, Dhaunkhola) Motar Road forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of Kanalichina (Pithoragarh) sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place: ~~Pithoragarh~~
Dated: ~~3.1.8.08~~
Chairman


Deputy Commissioner-cum-

District Level Committee

प्रारूप-30.2

परियोजना विवरण :— माननीय मुख्य मंत्री घोशणा संख्या 37/2015 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र डीडीहाट मे बुँगाछीना धौनखोला से रसैपाटा मोटर मार्ग का का नव निर्माण कार्य।

कार्यालय उप जिलाधिकारी, डीडीहाट

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण-पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति, डीडीहाट

उपखण्ड डीडीहाट परिक्षेत्र के अन्तर्गत माननीय मुख्य मंत्री घोशणा संख्या 37/2015 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र डीडीहाट मे बुँगाछीना धौनखोला से रसैपाटा मोटर मार्ग का का नव निर्माण कार्य (0.00 हे० आरक्षित वन भूमि, 0.810 हे० सिविल सोयम वन भूमि 0.000 हे० वन पंचायत भूमि, अर्थात कुल 0.810 हे० वन भूमि) का प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग पिथौरागढ़ प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील देवलथल) की दिनांक २५/०६/१० को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री ८५८८२५४१, उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

- | | | |
|----|--|---------|
| १- | श्री विजय चौधरी उपजिलाधिकारी | अध्यक्ष |
| २- | श्री अमरजीत सिंह प्रभागीय वनाधिकारी | सदस्य |
| ३- | श्री हरप्रीत कुलार्ह सहायक समाज कल्याण अधिकारी | सचिव |
| ४- | श्रीमती राधिका देवी बी०डी०सी० क्षेत्र | सदस्य |
| ५- | श्रीमती राधिका देवी पत्नी श्री कमान सिंह बी०डी०सी० क्षेत्र खाकोट सदस्य | |
| ६- | श्री उमेश सिंह पुत्र शेर सिंह बी०डी०सी० क्षेत्र जमतड़ सदस्य | |
| ७- | श्रीमती कमला देवी पत्नी श्री भुवन चन्द्र कापडी बी०डी०सी० क्षेत्र सतगढ़ सदस्य | |

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी द्वारा अनुसूचित बैठक की माननीय सदस्यों का अवगत कराया गया कि माननीय मुख्य मंत्री घोशणा संख्या 37/2015 परियोजना के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र डीडीहाट मे बुँगाछीना धौनखोला से रसैपाटा मोटर मार्ग का का नव निर्माण कार्य परियोजना हेतु 0.810 हे० वन भूमि प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग पिथौरागढ़ प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, डीडीहाट द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड डीडीहाट परिक्षेत्र के अन्तर्गत माननीय मुख्य मंत्री घोशणा संख्या 37/2015 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र डीडीहाट मे बुँगाछीना धौनखोला से रसैपाटा मोटर मार्ग का का नव निर्माण कार्य परियोजना हेतु 0.810 हे० वन भूमि प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग पिथौरागढ़ प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील- देवलथल
जनपद पिथौरागढ़

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, पिथौरागढ़ को भूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड रत्नीय वन अधिकार समिति
तहसील- देवलथल
जनपद पिथौरागढ़

*महान् प्र
हृषि पंचायत सतगढ़
जिला प्रिथौरागढ़ एवं उपखण्ड स्तरीय वन
अधिकारी की विवरण
तिथि २५/०६/१०*

परियोजना का नाम : माननीय मुख्य मंत्री घोषणा के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र डीडीहाट में दुंगाछीना धौनखोला रसैपाटा मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र
ग्राम पंचायत का नाम लालुकी (धनियाला, मुहर)

अनापत्ति प्रमाण पत्र
उत्तराखण्ड में माननीय मुख्य मंत्री घोषणा के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र डीडीहाट में दुंगाछीना धौनखोला रसैपाटा मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य परियोजना के निर्माण हेतु (0.00 हेतु आरक्षित वन भूमि, 0.810 हेतु सिविल सोयम भूमि, 0.000 हेतु वन पंचायत भूमि) अर्थात कुल 0.810 .हेतु वन भूमि का प्राप्त खण्ड लो० निः विः पिथौरागढ़ विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत लालुकी द्वारा दिनांक ०५/०५/२०१८ को सम्बन्ध ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपरिथित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

आमंत्रित

गोदाकर्ता-केरि

श्रावण

प्राप्त होने पर वन भूमि

ग्राम पंचायत/भरपूर उंगली

मुहर सहित

४०/-

ग्राम सचिव

ग्राम पंचायत प्रमाणित किया है।
क्षेत्र- डीडीहाट
दिक्षाय खण्ड